(ख) स्वीकृत लागत एवं निर्माण तिथियों इत्यादि को दर्शाती परियोजनाओं की सूची अनुपत्र में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र सं० 45]

(ग) जी नहीं, आगे कार्यान्वित नहीं किये जा सकने वाली परियोजनाओं की पहचान के लिए पुनर्प्राथमिकिकरण की प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Indo-Canadian Trade Ties

1096. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether steps have been taken by Government for the expansion of Indo-Canadian trade ties;

(b) if so, the number of deals signed with Canada during 1993-94, 1994-95 and 1995-96; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Government encourages Chambers of Commerce, Industry Associations, Export Promotion Councils, Commodity Boards etc. to take business delegations, organise buyer-seller meets, participate in each other's trade fairs and exchange business information with the Canadian Counterparts. In recent past, there have been high level visits from Canada including the visit of Canadian Prime Minister with large business delegation in January, 1996; visit of Mr. Roy Mac Laren, Canadian Minister for International Trade in October, 1994 and visit of Mr. Robert Huget, Minister for International Trade, Government of Ontario in February, 1995.

(b) and (c) As per DGCI & S, the position regarding trade with Canada during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 has been as follows:

(Value in Rs. Crores)

Year	Exports	Imports	Balance of Trade	Bilateral Trade
1993-94	714.65	735.69	(−) 21.04	1450.34
1994-95	836.30	822.02	(+) 14.28	1658.32
1995-96 (Upto Dec.)	738.76	864.19	(−)125.43	1602.95

The statistics on the number of deals signed is not maintained.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के लिए कोयला

1097. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपने विभिन्न उपक्रमों के जरिए प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और किस दर से नान कोकिंग कोल समेत कोयला भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) क्या आपूर्ति की जा रही कोयले की गुणवत्ता अच्छी नहीं है जिसके लिए प्राधिकरण ने सी०आई०एल० को कोयले की गुणवत्ता को सुधारने पर अधिक कीमत देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के एक उपक्रम द्वारा इसके दूसरे उपक्रम के साथ इस तरह की कार्रवाई का औचित्य क्या है और इस तरह की प्रयोगात्मक कार्रवाई से दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि०) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड "सेल" को प्रेषण दिये गये कोयले की कुल मात्रा जिसमें अकोककर कोयला भी शामिल है, 12.56 मिलियन टन किया गया था। चालू मूल दर जिस पर कि "सेल" को कोयला बेचा जाता है उसे नीचे दर्शाया गया है:

धुला कोयला : 213.67 रुपए से 1400.03 रुपए प्रति टन के बीच

सभी अन्य कोयला जिसमें अकोककर कोयला शामिल है उनका प्रशासित मूल्य के अनुसार बिक्री की जाती है।

(ख) और (ग) धुले हुए कोयले के मूल्य का निर्धारण "सेल" तथा कोल इंडिया लिमिटेड (को०इं०लि०) के बीच विचार-विमर्श करके द्विपक्षीय रूप में समझौता किया जाता है। वास्तविक रूप में मूल्य धुले कोयले में राख तत्व की विद्यमानता से जुड़ा हुआ है जिसकी कि आपूर्ति की जाती है।

बेहतर गुणवत्ता वाले कोयल के लिए अधिक मूल्य निर्धारित किया जाएगा। यह व्यवस्था कई वर्षों से चल रही है और यह कोई नयी व्यवस्था नहीं है। आपूर्ति किये जा रहे कोयले की गुणवत्ता में सुधार किये जाने के एक प्रयास के रूप में को०इं०लि० ने विभिन्न कदम उठाये हैं जिसमें निम्न कदम शामिल हैं:— विद्यमान वाशरियों का आधुनिकीकरण किया जाना तथा और अधिक वाशरियों का निर्माण किया जाना और डिशैलिंग संयंत्रों की स्थापना किया जाना।

Sugar Mills in Punjab

1098. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) state-wise details of licences issued for sugar mills during the last three years;

(b) the licences issued in Punjab for the above period, details thereof; and

(c) the criteria for issuing of licences?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) 76 letters of intent have been issued for setting up of new sugar mills and 35 for expansion of the existing units in the country during the last three sugar years (October-September) *i.e.* 1992-93, 1993-94 and 1994-95, the state-wise details of which are given below:-

S. No.	State	No. of letters of intent issued for establishment of new sugar factories	No. of letters of intent issued for expansion of capacity in the existing sugar units
1.	Haryana	4	1
2.	Uttar Pradesh	27	12
3.	Madhya Pradesh	2	1
4.	Gujarat	2	1
5.	Maharashtra	17	10
6.	Bihar	1	3
7.	Andhra Pradesh	15	—
8.	Karnataka	5	—
9.	Tamil Nadu	2	2
10.	Orissa	1	1
11.	Punjab	—	1
12.	Rajasthan	—	1
13.	West Bengal	—	2
		76	35

(b) During the last 3 years, one letter of intent for expansion of capacity from 5000 to 10,000 Tonnes cane crushing per day was issued to an existing unit, namely M/s. Oswal Agro Mills Ltd., Sugar unit at Phagwara, District Kapurthala, (Punjab).

(c) The applications for grant of letters of Intent Industrial Licences for establishment of new sugar factories and expansion in the existing sugar factories are considered in accordance with the licensing policy guidelines issued vide Press Note No. 16 dated 8.11.1991.

Closure of power plants due to coal shortage

1099. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of COAL be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1368 given in the Rajya Sabha on 14th August, 1995 and state the names and locations of power plants which have been closed for want of coal shortage?